अ0शा0 परिपत्र संख्याः एडीजी-02/2015

एच0सी0 अवस्थी
आई.पी.एस.

अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध),
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांक :जनवरी 28 , 2015

विषयः- Regarding better and effective implementation of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000, in the State of U.P.

प्रिय महोदय,

बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखने में पुलिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के प्रति पुलिस को अत्यधिक संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। सम्प्रति बच्चों के अधिकार, देख-रेख एवं संरक्षण के सम्बन्ध में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2000 एवं यथा संशोधित 2006 तथा केन्द्रीय नियमावली 2007 प्रचलित हैं, जिनमें अन्य प्राविधानों के अलावा थाने के बाल कल्याण अधिकारी एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई के कर्तव्य भी वर्णित हैं। यह अधिनियम उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पूर्व में किशोरों के विषय में अन्यान्य निर्देश इस मुख्यालय से निर्गत किये गये है। इस परिपत्र के माध्यम से पुनः बाल कल्याण/विशेष पुलिस इकाई के विषय में मा0 उच्च न्यायालय की अपेक्षानुसार अवगत कराया जा रहा है।

2- उपर्युक्त विषय में मा0 उच्च न्यायालय की सम्मानित कमेटी जो Juvenile Justice(Care and Protection of Children) Act, 2000 के बेहतर व प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित हुयी थी, के द्वारा दिनांक 18.12.2014 की बैठक में कतिपय निर्णय लिये गये थे, जिसकी प्रति आपको संलग्न कर प्रेषित भी की जा रही है। मा0 उच्च न्यायालय की उपर्युक्त कमेटी द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि समस्त निष्कर्षो का कठोर व अक्षरशः अनुपालन व क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय तथा तद्विषयक प्रगति आख्या भी प्रेषित की जाय, ताकि कृत कार्यवाहियों व प्रगति से मा0 उच्च न्यायालय को समय से अवगत कराया जा सकें।

3. किशोर न्याय के मामलों में उक्त समिति द्वारा पुलिस की उदासीनता पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निम्न टिप्पणी की गयी हैः-

- जनपद मेरठ में दिनांक 11.12.2014 को किशोरों के साथ घटित घटना के परिप्रेक्ष्य में मा0 कमेटी द्वारा यह टिप्पणी दी गयी कि अभी भी किशोर का चालान गैम्स्टर एक्ट में किया जा रहा है, जो अनुचित है।
- पुलिस की मानसिकता बाल अपराधियों के प्रति अभी भी सुधारात्मक न होकर दण्डात्मक ही है
- बाल मित्र/बाल कल्याण अधिकारी अधिकांशतः बाल गृहों एवं किशोर न्यायिक प्रक्रिया में अनुपस्थित रहते है।
- बाल मित्र/बाल कल्याण अधिकारियों द्वारा किशोरों के केसों की कार्यवाही बावर्दी की जा रही है, जो अनुचित है।
- गवाह भी न्यायिक प्रक्रिया में निर्धारित तिथियों में अधिकतर उपलब्ध नहीं रहते है, जिसके परिणाम स्वरूप बाल अपराधों के प्रकरण काफी दिनों तक लम्बित बने रहते है व रिमाण्ड की अनवरतता बनी रहती है।

4. समिति द्वारा प्रकाश में लाये गये उपरोक्त टिप्पणी के आलोक में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जा रहे है:-

- बाल कल्याण अधिकारियों को यूनीसेफ एवं गैर सरकारी संस्थाओं(एन0जी0ओ0) के सहयोग से प्रशिक्षित कराया जाय, जिससे बाल मित्र, संवेदनशील तथा बच्चों के प्रति मित्रता पूर्ण व्यवहार और जे0जे0एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए बच्चों के प्रति संवेदनशील बनाया जाय।
- बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के दृष्टिगत उनका पुनर्वास किया जाय, जिससे वह गलत संगत में न पड़े, पुनः अपराध कारित न करें और अपने स्व गृह से पलायन न करें। साथ ही बाल कल्याण अधिकारी की उपस्थिति बाल संरक्षण संस्थान में सुनिश्चित की जाय।
- प्रशिक्षित बाल कल्याण अधिकारियों का जल्दी-जल्दी स्थानांतरण न किया जाय। अगर किन्ही परिस्थितियों में बाल कल्याण अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो इनके स्थान पर उचित प्रतिस्थानी की नियुक्ति के बाद ही स्थानांतरित किया जाय।
- बाल किशोर न्यायालय अथवा जहॉ आवश्यकता हो एवं इनके गृह राज्य/गृह जनपद हेतु बाल अपराधियों के आवागमन के समय से पुलिस स्कोर्ट समय से प्रदान किया जाय।
- बाल अपराधियों को वयस्क/अभ्यस्त अपराधियों के साथ आवागमन न कराया जाय।
- बाल अपराधियों के प्रकरणों में उनके विरूद्ध किसी भी दशा में गैगेंस्टर अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही न किया जाय।

5- एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप अपरोक्त सभी निर्दिष्ट बिन्दुओं का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करेगें। उचित होगा कि जनपद में मासिक अपराध समीक्षा एवं कार्यशाला आयोजित कर अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस परिपत्र में निर्गत निर्देशों से भली-भॉति अवगत करा दिया जाय। यदि किन्ही अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा **बच्चों के अधिकार, देख-रेख एवं संरक्षण के सम्बन्ध में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2000 एवं यथा संशोधित 2006 तथा केन्द्रीय नियमावली 2007** में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने में किसी भी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही दृष्टिगोचर होती है तो उनकी समीक्षा कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय। कृत कार्यवाहियों की प्रगति से समय-समय पर इस मुख्यालय को अवगत कराया जाय।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवन्निष्ठ,

(एच0सी0 अवस्थी)

1-समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (नाम से),
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज, उ0प्र0 (नाम से)

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण/नोडल अधिकारी किशोर न्याय(बालको की देख-रेख एवं संरक्षण), उ0प्र0 ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
3. जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0

MOST URGENT

~~By Registered Post~~

Spl. Messenger

From,

Narendra Bahadur Yadav, H.J.S.,
Joint Registrar (J) (Inspection),
High Court of Judicature at ,
Allahabad.

To

1- Smt. Renuka Kumar, Principal Secretary,
Women & Child Development, Govt. of U.P., Lucknow.
2- Ms. Kamini Ratan Chauhan, Secretary Finance,
Govt. of U.P.,Lucknow.
3- The Principal Secretary, Medical & Health Department,
Government of U.P., Lucknow.
4- The Principal Secretary, (Technical Education), Govt. of U.P.,
Lucknow.
5- The Secretary, Primary Education, Govt. of U. P., Lucknow.
6- Mr. D.N. Verma, Director, Women & Child Welfare, U.P.,
Lucknpw.
7- Mr. S. K. Srivastava, Director, Handicapped Welfare, U.P.,
Lucknow.
8- Director General of Police / I.G.(In-charge of Juvenile matters),
Govt. of U.P., Lucknow.
9- Mr. Ashok Kumar Mishra, Chief Probation Officer, Uttar Pradesh,
Lucknow.
10- Mr. Sudhir K. Rai, I.C.P.S. Consultant, U.N.I.C.E.F., Govt. of
U.P., Lucknow.
11- Mr. Tej Pratap Tewari, H.J.S., Secretary, U.P.S.L.S.A., Lucknow.
12- Mr. S.K. Mishra, Deputy C.P.O. , Women welfare, Govt. of U.P.,
Lucknow.
13- Mr. Manish Singh, Police Training Consultant, U.N.I.C.E.F., Govt.
of U.P., Lucknow.
14- Ms. Tanishtha Dutta, Child Protection Specialist, U.N.I.C.E.F., Govt. of U.P.,
Lucknow.

No. 667 /Main-B/Admin. (A-3)/ Allahabad:Dated:January 16, ,2015.

Subject :- **Regarding better and effective implementation of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000, in the State of U.P..**

Sir/Madam,

On the above noted subject, I have been directed to enclose herewith a copy of the resolution dated 18.12.2014 of the meeting of Hon'ble Committee, constituted for Monitoring of the better and effective implementation of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000, in the State of Uttar Pradesh.

I am, therefore, to request you to kindly ensure strict compliance of the above mentioned resolution dated 18.12.2014 of Hon'ble Committee and submit your progress/compliance reports, in the matter, **to the Court, immediately**, so that the same may be placed before Hon'ble the Committee, in the next meeting which is fixed in the 1st week of February, 2015.

Yours faithfully,

16/1/15

Joint Registrar (J.) (Inspection)

Encl.:- As above.

पुलिस महानिदेशक कार्यालय
उत्तर प्रदेश 19/1/15

Sensitization of Police Child Welfare Officers and for providing escorts for the ailing children in home and for presenting witness etc.	The Committee records its displeasure at the police indifference in juvenile justice matters. The DIG (Allahabad Range) was not properly briefed and could not answer the queries raised by the Committee. Culpability of the police for violence against the juveniles in custody was writ large on the Meerut incident of 11.12.14. Police are still challonging juveniles under the Gangsters Act which is clearly unacceptable. The mindset of police against juveniles is still retributive and not reformative. Child friendly Child/ Juvenile Welfare Police Officers are usually absent from homes or in Juvenile Justice proceedings They usually deal with juveniles and children in uniforms, which is not legally permissible. Witnesses are not available on the dates fixed, which often results in continuing remands of the juveniles as the disposal of their matters are held up. Police escorts are not available for long periods for taking poor children whose parents are not appearing to their home States or natal homes, causing them to languish in children's homes for long periods. [redacted] into and to remedy all these issues, and to take steps for training the JCWOs with aid from UNICEF and other mentor NGOs to make the JCWOs more child friendly and sensitive, and regarding the provisions under the JJ Act and Rules, including preparation of proper social investigation reports and for effective future rehabilitation of the juveniles/ children so that they do not again fall in bad company and commit offences or flee from their natal homes, and to ensure the presence of JCWOs in the CCIs. Good juvenile welfare officers after getting training should not be speedily transferred to other jobs without proper alternative arrangements. Timely escorts be provided for taking juveniles to the JJBs or wherever escorts are required, and for escorting children in need of care and protection to their home States or natal homes. The Police and Home departments be directed not to transport juveniles with adult prisoners when transporting the juveniles to the CCIs or to the Juvenile Justice Boards. Juveniles be not challaned under the Gangsters Act. Action be taken against the culpable police officers in the Meerut incident, and against other police personnel who engage in violence against juveniles and follow a retributive and non-reformatory approach against juveniles and monitoring be done and culpability be fixed for all police misdeeds or inaction in matters
	relating to juveniles and children. On the next Committee meeting the I.G. (in-charge of juvenile matters) be present and properly brief the Committee regarding queries raised and report compliance of the aforesaid directions.

...Sensitization of Police Child Welfare Officers and for providing escorts for the ailing children in home and for presenting witness etc.	The Committee records its displeasure at the police indifference in juvenile justice matters. The DIG (Allahabad Range) was not properly briefed and could not answer the queries raised by the Committee. Culpability of the police for violence against the juveniles in custody was writ large on the Meerut incident of 11.12.14. Police are still challonging juveniles under the Gangsters Act which is clearly unacceptable. The mindset of police against juveniles is still retributive and not reformative. Child friendly Child/ Juvenile Welfare Police Officers are usually absent from homes or in Juvenile Justice proceedings They usually deal with juveniles and children in uniforms, which is not legally permissible. Witnesses are not available on the dates fixed, which often results in continuing remands of the juveniles as the disposal of their matters are held up. Police escorts are not available for long periods for taking poor children whose parents are not appearing to their home States or natal homes, causing them to languish in children's homes for long periods. [redacted]nto and to remedy all these issues, and to take steps for training the JCWOs with aid from UNICEF and other mentor NGOs to make the JCWOs more child friendly and sensitive, and regarding the provisions under the JJ Act and Rules, including preparation of proper social investigation reports and for effective future rehabilitation of the juveniles/ children so that they do not again fall in bad company and commit offences or flee from their natal homes, and to ensure the presence of JCWOs in the CCIs. Good juvenile welfare officers after getting training should not be speedily transferred to other jobs without proper alternative arrangements. Timely escorts be provided for taking juveniles to the JJBs or wherever escorts are required, and for escorting children in need of care and protection to their home States or natal homes. The Police and Home departments be directed not to transport juveniles with adult prisoners when transporting the juveniles to the CCIs or to the Juvenile Justice Boards. Juveniles be not challaned under the Gangsters Act. Action be taken against the culpable police officers in the Meerut incident, and against other police personnel who engage in violence against juveniles and follow a retributive and non-reformatory approach against juveniles and monitoring be done and culpability be fixed for all police misdeeds or inaction in matters
	relating to juveniles and children. On the next Committee meeting the I.G. (in-charge of juvenile matters) be present and properly brief the Committee regarding queries raised and report compliance of the aforesaid directions.